

age". In that spirit this film has been created. All other things have been taken care of.

MR. CHAIRMAN: Next question Question No. 184.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT: H;»s h<; consulted Vinoba Bhavaji?

Suggestions from petroleum conservation research association for saving petrol consumption by vehicles

*184. SHRI KALRAJ MISHRA:t
SHRI SUNDER SiNGH
BHANDARI:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a press report published in the 'Statesman' dated the 16th September, 1980 that the Petroleum Conservation Research Association has suggested some efficient driving practices and better maintenance of vehicles which "can save for India 6 per cent of the total oil consumed; and

(b) if so, whether Government have issued any instruction to implement these suggestions, so far as Government vehicles are concerned?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) It is true that the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) has identified a potential for saving 6 per cent in commercial diesel driven vehicles, if recommended efficient driving and maintenance practices are followed. For this purpose, the PCRA has initiated steps to educate the drivers and owners of such vehicles about better driving and maintenance practices. Besides, on the advice of this Ministry, the Ministry of Shipping and Transport had written in 1977 to all the State Governments and Union Territories about

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kalraj Mishra.

placing limits on the speed of the vehicles. The speed limits suggested are; 40 Kms. per hour for passenger vehicles (buses) and 60 Kms. per hour for goods vehicles (trucks) of the State Transport Undertakings.

श्री कलराज मिश्र : श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान की सिफारिशें जो सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर सरकार को दी गई हैं जो पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए किया जा सकता है, क्या उनका पालन किया गया है और अगर हां तो किस हद तक ?

दूसरा, इसी से संबंधित प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि अनुसंधान संस्थान की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकारी वाहनों में किस हद तक तेल की बचत हो सकी है ? अभी मंत्री महोदय ने यह बताया, कुछ जो सिफारिशों को लागू करने की बात विभिन्न विभागों की तरफ से कही गई है, क्या इसकी जानकारी करने की दृष्टि से जो प्रयत्न हुआ है उसके बारे में मंत्री महोदय को पता है कि वह किस हद तक हुआ है ?

श्री पी० सी० सेठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक उन सिफारिशों का ताल्लुक है, जैसा प्रश्न के मूल उत्तर में बताया गया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा राज्य सरकारों को भी लिखा गया और इसके संबंध में काफी विस्तृत पैम्फलेट्स भी निकाले गए हैं, जो छपे हुए हैं—शायद माननीय सदस्य ने देखे होंगे—उनकी जानकारी के लिए मैं और दे सकता हूँ। लेकिन जहां तक सवाल है कि इससे बचत कितनी हुई या उसमें इम्प्रूवमेंट कितना हुआ इसकी कोई खास मानीटरिंग हो नहीं पायी है इसलिए मुझे अफसोस है मैं ये फिर्स दे नहीं सकूंगा। किंतु बचत इसकी वजह से हुई है और जो मांडल डिपोज़ इसके बारे में बनाए गए थे उनमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि छः से ग्यारह परसेन्ट तक की डीज़ल की बचत हो सकती है अगर उन निदर्शों के अनुसार

डाइविंग किया जाए और जो स्मोक आदि निकलता है उनको रोका जाए और गाड़ियों की वेंटीनेन्स को अच्छा रखा जाए ।

श्री कलराज मिश्र : श्रीमन्, इसमें "स्टेट्समैन" का 16 सितम्बर का यह पी० सी० आर० ए० का एक नोट है, इसमें इन्होंने रिकमण्डेशन दिया है । इसमें केवल रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में ही नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टेक्सटाइल इन सारी चीजों के बारे में दिया है । अगर इसमें लिखी सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया जाए तो डीजल की खपत में बचत आ सकती है । इस संबंध में मैं आपको इसी अखबार से पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ जिसमें यह दिया गया है कि—

"The PCRA has studied nearly 195 industrial units which together consume 2.78 million kilolitres of furnace oil and has offered recommendations on various aspects of 12 efficiency practices. The studies have identified a saving potential of 3,60,000 kilolitres of furnace oil. It has stated that saving of 1,60,000 kilolitres has already been achieved by the users."

तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो पी० सी० आर० ए० की तरफ से सिफारिश की गई है, और मंत्री जी ने 6 परसेन्ट बचत की बात बताई और यह कि जो यूजर्स हैं, डाइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, यदि वे ठीक ढंग से चेतन्य होकर काम करें तो उचित बचत हो सकती है, यह रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में मंत्री महोदय ने बताया किन्तु इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस प्रकार की रिकमण्डेशन पी० सी० आर० ए० की तरफ से है, शायद उसके संबंध में मंत्रालय की तरफ से किसी प्रकार से कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे बचत हो सकती है, उसकी सिफारिशों को किस तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है ? मैं सोर्स जानना चाहता हूँ, माध्यम जानना चाहता हूँ ।

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया था वह मूलतः कन्जर्वेशन आन एकाउन्ट आफ एफीशिएंट डाइविंग एण्ड बेटर मॅन्टेनेस आफ वेहिकिल्स था । इसलिए उसके सम्बन्ध में जो दूसरा मूल प्रश्न अब उन्होंने पूछा है ..

श्री कलराज मिश्र : श्रीमन्, मैंने 16 सितम्बर के "स्टेट्समैन" का हवाला देकर प्रश्न किया है । उसमें वह सारी चीजें आ गयी हैं जो अभी मैंने सवाल किया है ।

श्री पी० सी० सेठी : 'स्टेट्समैन' में जो पी० सी० आर० ए० की रिपोर्ट छपी है वह सही है ।

श्री कलराज मिश्र : मैं यह जानना चाहता था कि जो रिपोर्ट छपी है स्टडी के परिणाम-स्वरूप उसके इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से मंत्रालय ने क्या किया है ?

श्री पी० सी० सेठी : सभापति महोदय, इस सवाल के सम्बन्ध में एक दफा पहले भी मैंने बताया था कि करीब 295 इंडस्ट्रीज में फर्नेस आयल बचाने की कोशिश की गयी है और कइयों को फर्नेस आयल से कोल पर स्विच आन कर दिया है । इसी प्रकार कोशिश यह है कि कुछ पावर हाउसेज, जो फर्नेस आयल पर चलते हैं, उनको भी कोल पर कन्वर्ट किया जाये । उस रोज माननीय सदस्य श्री कल्याण राय ने यह सवाल किया था कि क्या इस बीच में कुछ पार्टीज को फ्युएल आयल दिया गया है । तो यह बात सही है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का कहना है कि कोई 8-9 सीमेंट कम्पनीज को फ्युएल आयल दिया भी है । तो कुल मिला कर इस बात की कोशिश है कि इस संस्थान ने जो सिफारिशें की हैं डाइविंग प्रेविटसेज के बारे में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहां कहीं भी किरोसिन की, डीजल की बचत हो सकती है उसके बारे में बराबर

परीक्षण किया जा रहा है। फ्युएल आयल या इस पर आधारित कोई इंडस्ट्री लगाने के बारे में एक कमेटी है। जब वह क्लियरेंस देती है तभी इसके आधार पर नया उद्योग लगने दिया जाता है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : पेट्रोलियम अनुसंधान संघ ने जो सिफारिशें की हैं उसमें एक सिफारिश है 'यूज आफ अलकोहल एण्ड पेट्रोल मिक्सचर फार आटोमोबाइल इंजिन्स'। अभी पिछले दिनों 20 अक्टूबर को आई० आई० टी० में एक सेमिनार हुआ था। सेठी जी के पूर्व जो मिनिस्टर साहब थे श्री पाटिल उन्होंने वहां यह कहा था कि अगर हम आटो-मोबाइल इंजिन्स के लिए अलकोहल का इस्तेमाल करेंगे तो जो फूड प्रोड्यूसिंग एरिया है उसको घटा कर हमें अलकोहल बनाने वाली चीजों को उगाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा जब कि इस सिफारिश में यह साफ तौर पर कहा गया कि एग्रीकल्चरल वेस्ट और पेपर इंडस्ट्री के पल्प और मोलासेज से ही बहुत बड़ी मात्रा में एलकोहोलिक गैस तैयार की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर करीब-करीब 35 परसेंट पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कन्ज्यूम करता है तो इस गैस का इन्ट्रोडक्शन पेट्रोल के कन्जम्शन को बचाने के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। मैं वर्तमान मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो पूर्वग्रह था कि अगर गैस के लिए अलकोहल का इस्तेमाल करेंगे तो फूड प्रोडक्शन पर एडवर्स असर पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में मिनिस्ट्री की थिंकिंग रिवाइज हुई है या नहीं? अगर वह रिवाइज हुई है तो एग्रीकल्चरल वेस्ट और पेपर पल्प मोलासेज का इस्तेमाल करके अलकोहल गैस को मोटर, स्कूटर, मोटर-साइकिल और इस तरह के वेहिकल्स में इस्तेमाल करने के बारे में अब सरकार का क्या विचार है?

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सभापति महोदय, यह परीक्षण हो चुका है कि मोटर

स्परिट के साथ करीब 20 परसेंट अलकोहल मिलाया जा सकता है। इससे अधिक मिलाने से मोटर इंजिन के खराब हो जाने का खतरा है। मगर इस समय सवाल यह है कि अलकोहल में भी दो प्रकार के अलकोहल बनते हैं—एक पोटैबिल अलकोहल है बिच इज यूज्ड फार ड्रिंकिंग परपज्ज, दूसरा इंडस्ट्रियल अलकोहल है। इस समय आम तौर पर राज्य सरकारें अपने एक्साइज रेवेन्यू की आमदनी को मद्देनजर रखते हुए पोटैबिल अलकोहल ज्यादा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस प्रकार इंडस्ट्रियल अलकोहल की कमी है। एक शार्ट सप्लाय के आइटम को दूसरे शार्ट सप्लाय के आइटम से मीट करना मुश्किल है।

जहां तक भंडारी साहब ने यह सवाल उठाया कि अलकोहल दूसरी चीजों से बनाया जा सकता है, इस बात का भी परीक्षण हो रहा है। उदाहरण के तौर पर टेपियाको या दूसरे एग्रीकल्चरल वेस्ट से भी अलकोहल बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए टेपियाको की खेती बढ़ानी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो अलकोहल बनेगा उसके सम्बन्ध में अभी कोई खास अलकोहल बनाने का परीक्षण नहीं हुआ है। जो वेस्ट है उसके आधार पर गैस बनाने का और गांवों में एनर्जी सप्लाय करने का काफी परीक्षण हो चुका है और उस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है, लेकिन एग्रीकल्चरल वेस्ट से अलकोहल बनाने का कोई ठोस उदाहरण सामने नहीं आया है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : इसकी वजह क्या है कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से गैस बनाने का मामला परखू नहीं किया जा रहा है जब कि ऐक्सपर्ट ओपीनियन इसके फेवर में है?

SHRI P. C. SETHI: It is because petrol is one thing and alcohol is another thing.

MR. CHAIRMAN: It cannot be combined with petrol.

एक ही कर सकते हैं कि जो पासिबल अल्कोहल है उसके बदले पेट्रोल पिलाया जाए।

श्री रामेश्वर सिंह : सभापति जी, मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि पेट्रोल की बचत के लिए विभिन्न सोसों पर विचार किया जा रहा है या सरकार का ध्यान इस ओर है ? क्या कारण है कि सरकार, जैसे जापान और अमरीका जैसे शक्तिशाली देश मिनी कार, छोटी कार बनाकर 75 किलोमीटर से 80 किलोमीटर चलाकर गाड़ी से 50 परसेंट पेट्रोल की बचत कर सकते हैं यहां पर अभी तक सरकार ने बड़े हाउसेज को ही इसके लिए इजाजत दी है कि वह अपनी गाड़ी भले ही वह 30 मील चले, 40 मील चले, उस गाड़ी का दाम 60 हजार रुपये हो गया है, उस कीमत पर बेचें फिर भी आज्ञादी के 30-33 वर्ष बाद भी जब कि पेट्रोल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है तो सरकार ने क्यों नहीं ऐसा फारमूला बनाया अपने मातहत या दूसरी इंडस्ट्रीज के मातहत जिससे पेट्रोल की खपत 50 परसेंट कम हो सके ? क्या एक ही व्यक्ति के हाथ में मोनोपली देकर सरकार चलाना चाहती है ?
(Interruptions)

श्री पी० सी० सेठी : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में संबंधित मंत्रालय जो गाड़ी का उत्पादन करते हैं उनको लिखा है कि मोटर इंजिन में इस प्रकार के सुधार किये जायें जिससे कि वह अभी जो माइलेज देती है उससे ज्यादा दें चाहे वह ट्रक्स हों, बसें हों या कारें हों। जहां तक छोटी गाड़ी का सवाल है, मैंने अभी तक कोई ऐसी गाड़ी के बारे में नहीं सुना जो 60 मील, 70 मील चली।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मैं ने कहा है 70 किलोमीटर। मैंने वह गाड़ी देखी है। मैं इनको बता दूँ।... (Interruptions)

श्री सभापति : मील और किलोमीटर में फर्क हो गया है।... (Interruptions)

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मैंने इनको बता दिया है कि यह गाड़ी मैंने खुद देखी है। जो इन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा है वहां एम्बेसी की गाड़ियां आती हैं वह बेचते हैं। यह धंधा चल रहा है। मेरा कहना है कि छोटी गाड़ी बनाकर 50 परसेंट जापान में और अमरीका में और छोटे-छोटे देश जर्मनी में 85-85 किलोमीटर, 60 किलोमीटर नहीं, 85 किलोमीटर तक एक गाड़ी का एवरेज है। उस पर आपने क्या विचार किया है ?

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यह जानकारी दी। मैं इस सम्बन्ध में संबंधित मंत्रालय को यह जानकारी बता दूंगा।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मैंने सवाल पूछा है कि क्या कारण है कि बड़े हाउसेज को एक बड़े उद्योगपति विड़ला साहब को आपने, इजाजत दे रखी है मुल्क में दामों की लूट करने की ? क्या यही कारण है जिसके कारण आपने दूसरी गाड़ी नहीं निकाली ?

SHRI P. C. SETHI: This is not the Ministry dealing with cars.

श्री सभापति : आपका आधा मिनट है और आधे मिनट के लिये शोर ही जाएगा तीन मिनट का।

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT: Sir, the hon. Minister has said that 6 to U per cent saving can be effected if the suggestions that have been made are put into effect. If there anytime limit within which these savings can be effected? Has the Government laid down any time limit? Is there any definite programme to bring about savings? Otherwise the reply gives the impression that these are useful suggestions which have been passed on to the States? This seems to be a casual approach towards a very vital area of conservation. Will the Government pin down the conservation aspect and bring down consumption

by 6 to 11 per cent? Will the Minister let us know how he is going to do that?

SHRI P. C. SETHI; Sir, we are trying to do it only in advisory manner. But apart from that, I may like to draw the attention of the hon. Member to this point that we have opened model depots for these jobs. Apart from that, the PCRA has trained about 23 fleet, consisting of about 6000 buses and more than a thousand drivers on these. Sir, this question was asked by the hon. Member the other day as to whether we wanted to do it by legislation. No, we would like to do it by vigorous persuasion, and not by legislation.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over by all the watches and clocks I have access to.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Earning-through Commercial advertisements on AIR/Doordarshan

*185. SHRI GURUDEV GUPTA:
SHRIMATI HAMIDA HABI-
BULLAH:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the details of the earnings by the All India Radio and Doordarshan separately through commercial broadcasting during the year 1979-80;

(b) the estimated earnings from these sources during 1980-81; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to further increase the earnings through commercial broadcasting?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) A.I.R., Rs. 10,29,57,588.00 (Gross earnings)

Doordarshan Rs. 6,16,43,839.95 (Gross earnings)

(b) A.I.R. Rs. 11,00,00,000.00 (Gross earnings)

Doordarshan Rs. 7,50,00,000.00 (Gross earnings).

(c) Some of the proposals under consideration are:—

(i) Revision and rationalisation of rate structure for commercials;

(ii) Introduction of commercial advertising to a limited extent on the primary broadcasting channels of All India Radio;

(iii) Augmentation of existing recording facilities at Doordarshan Kendras;

(iv) Introduction of new Doordarshan programmes produced by advertisers for sponsorship.

Cost Audit Reports

*186. SHRI KALYAN ROY:
SHRI BHOLA PRASAD:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1181 given in the Rajya Sabha on the 11th August, 1980 and state:

(a) whether a final decision regarding revealing the information in the cost audit reports" so far carried out in various industries has been taken;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons for this inordinate delay; and how long Government would take to decide the matter?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHIV SHANKAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

No final decision has yet been reached on the question, which involves confidentiality of information